



Lakshya IAS

academy

15

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट २०२६ एक अक्टूबर से 1. प्रभावी

बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, २०२६ एक अक्टूबर, २०२६ से लागू होगा, जो १८९१ के कानून का स्थान लेगा। यह अदालती कार्यवाहियों में बैंकिंग अभिलेखों के उपयोग के लिए एक प्रौद्योगिकी-तटस्थ ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी और क्लाउड-आधारित अभिलेख शामिल हैं। यह अधिनियम अभिलेखों के हस्तचालित, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। इसके तहत अदालतों को बैंक अधिकारियों को उस समय बुलाने से पहले एक रविशेष कारण निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता होती है जब बैंक किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है। केंद्र सरकार इसके प्रावधानों को कुछ वित्तीय संस्थानों तक भी विस्तारित कर सकती है।



मुख्य बिंदु:

- बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, २०२६ एक अक्टूबर, २०२६ से लागू होगा, जो १८९१ के अधिनियम का स्थान लेगा और अदालती कार्यवाहियों में बैंकिंग अभिलेखों के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- यह भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी और क्लाउड-आधारित बैंकिंग अभिलेखों को मान्यता देता है, जिसमें हस्तचालित, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति है।
- जब बैंक कार्यवाहियों में कोई पक्षकार नहीं होता है, तो बैंक अधिकारियों को बुलाने से पहले अदालतों को लिखित में रविशेष कारण दर्ज करना अनिवार्य है।

Bankers' Books Evidence Act 2026 Effective October 1

The Bankers' Books Evidence Act, 2026 will come into force on October 1, 2026, replacing the 1891 law. It introduces a technology-neutral framework for using banking records in court proceedings, covering physical, electronic, digital, virtual and cloud-based records. The Act allows manual, digital and electronic certification of records. It also requires courts to specify a "special cause" before summoning bank officials when the bank is not involved in a case. The Central Government may extend its provisions to certain financial institutions.



Key Points:

- The Bankers' Books Evidence Act, 2026 will come into force on October 1, 2026, replacing the 1891 Act and providing a modern legal framework for banking records in court proceedings.
- It recognises physical, electronic, digital, virtual and cloud-based banking records, with certification permitted through manual, digital or electronic signatures.
- Courts must record "special cause" in writing before summoning bank officials when the bank is not a party to the proceedings.

2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ७४५.७ अरब

अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा

✎ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नवीनतम

सप्ताह में बढ़कर ७४०.८०* अरब

अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसे मुख्य

रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में तेज वृद्धि से समर्थन मिला,

जो ४७.४९८ अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर ६४८.१६८ अरब

अमेरिकी डॉलर हो गई। यह वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक की

विशेष विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा खिड़की के माध्यम से

भारी आवक के बाद हुई, जिसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने के

बाद समय से पहले बंद कर दिया गया था। हालांकि, भारत का

स्वर्ण भंडार २.५९४ अरब अमेरिकी डॉलर घटकर

११*८१६ अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकार होल्डिंग्स मामूली

रूप से घटकर १८.८०६ अरब अमेरिकी डॉलर हो गई।



मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के रियायती विदेशी मुद्रा विनिमय उपायों के बाद विदेशी मुद्रा प्रवाह में वृद्धि के चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ७४०.८०* अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में ४७.४९८ अरब अमेरिकी डॉलर की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, जो ६४८.१६८ अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा खिड़की ने इस प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- भारत का स्वर्ण भंडार २.५९४ अरब अमेरिकी डॉलर घटकर ११*८१६ अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकार होल्डिंग्स मामूली रूप से घटकर १८.८०६ अरब अमेरिकी डॉलर हो गई।

2. India's Forex Reserves Reach Record

USD 785.7 Billion

✎ India's foreign exchange

reserves surged to USD

740.803 billion in the

latest week, supported

mainly by a sharp rise in foreign currency

assets (FCAs), which climbed by USD

47.498 billion to USD 648.168 billion. The

increase followed substantial inflows

through the RBI's special FCNR(B) deposit

window, which was closed early after

achieving its objective. However, India's

gold reserves declined by USD 2.594 billion

to USD 113.816 billion, while SDR holdings

with the IMF fell marginally to USD 18.806

billion.



Key Points:

- India's foreign exchange reserves jumped to a record USD 740.803 billion, supported by a rise in foreign currency inflows following the RBI's concessional forex swap measures.
- Foreign Currency Assets (FCAs) recorded the biggest increase of USD 47.498 billion, reaching USD 648.168 billion. The FCNR(B) deposit window contributed significantly to the inflows.
- India's gold reserves declined by USD 2.594 billion to USD 113.816 billion, while SDR holdings with the IMF fell marginally to USD 18.806 billion.

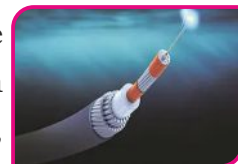
3. भारत और अमेरिका ने समुद्र के नीचे के केबल सुरक्षा सहयोग को किया सुदृढ़

भारत और अमेरिका वैश्विक सब-सी केबल नेटवर्क की सुरक्षा, लचीलेपन और विविधता में सुधार के लिए सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, जो डिजिटल संचार, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा केंद्रों, ई-कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समर्थन करते हैं। इस साझेदारी को भारत-अमेरिका ट्रस्ट पहल के तहत आयोजित एक अंडरसी केबल्स कार्यशाला के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति इसे एक संभावित वैश्विक सब-सी अवसंरचना केंद्र बनाती है। यह सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना, अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों और उन्नत कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करने के द्विपक्षीय प्रयासों का भी पूरक है।



India, US Deepen Undersea Cable Security Cooperation

India and the US are strengthening cooperation to improve the security, resilience and diversity of global undersea cable networks, which support digital communication, cloud computing, data centres, e-commerce and AI. The partnership was advanced through an Undersea Cables Workshop held under the US-India TRUST Initiative. India's growing digital economy and strategic location make it a potential global subsea infrastructure hub. The collaboration also complements bilateral efforts to expand AI infrastructure, next-generation data centres and access to advanced computing resources.



मुख्य बिंदु:

- भारत और अमेरिका वैश्विक समुद्र के नीचे के केबल प्रणालियों की सुरक्षा, लचीलेपन और विविधता को बढ़ाने के लिए सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, जो डिजिटल संचार, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा केंद्रों, ई-कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समर्थन करते हैं।
- भारत-अमेरिका ट्रस्ट पहल के तहत, दोनों देशों ने एक अंडरसी केबल्स कार्यशाला आयोजित की, जिसमें भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण सब-सी डिजिटल अवसंरचना के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।
- यह सहयोग अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों, कंप्यूटिंग संसाधनों और सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना में तेजी लाने के लिए भारत-अमेरिका रोडमैप का पूरक है।

Key Points:

- India and the US are strengthening cooperation to enhance the security, resilience and diversity of global undersea cable systems, which support digital communication, cloud computing, data centres, e-commerce and AI.
- Under the US-India TRUST Initiative, both countries held an Undersea Cables Workshop, highlighting India's potential to become a major global hub for subsea digital infrastructure due to its growing digital economy and strategic geographical location.
- The collaboration complements the US-India Roadmap for Accelerating AI Infrastructure, focusing on next-generation data centres, computing resources and secure digital connectivity.

4. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुजरात ने चौबीसों घंटे दुकानें खोलने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया

✎ गुजरात विधानसभा ने व्यापार नियमों को सरल बनाने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए पांच राज्य



कानूनों के १२ प्रावधानों में संशोधन करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक २०२६ पारित किया है। प्रमुख उपायों में पात्र प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे सातों दिन संचालित करने की अनुमति, व्यापार पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा, जोखिम-आधारित अग्नि सुरक्षा नियम और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूत सहायता शामिल है। यह विधेयक विलंबित सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्वचालित अपील भी शुरू करता है और अन्य राज्यों के डॉक्टरों के लिए पंजीकरण को सरल बनाता है। इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन के बोझ को कम करना, मंजूरीयों में तेजी लाना और व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- गुजरात विधानसभा ने व्यावसायिक मंजूरीयों, अनुपालन और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए पांच राज्य कानूनों के १२ प्रावधानों में संशोधन करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, २०२६ पारित किया।
- प्रमुख सुधारों में पात्र वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चौबीसों घंटे सातों दिन संचालन, नए व्यापार पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा, जोखिम-आधारित अग्नि सुरक्षा मानदंड, विस्तारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा और विलंबित सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्वचालित अपील शामिल हैं।
- यह विधेयक स्व-घोषणा के माध्यम से अन्य राज्यों के डॉक्टरों के त्वरित पंजीकरण को भी सक्षम बनाता है, जिससे गुजरात में पेशेवर पंजीकरण आवश्यकताओं में ढील मिलती है।

4. Gujarat Passes Bill Allowing 24×7 Shops to Boost Business

✎ The Gujarat Assembly has passed the Ease of Doing Business Bill 2026, amending 12 provisions



across five state laws to simplify business regulations and improve public services. Key measures include allowing eligible establishments to operate 24/7, self-declaration for business registration, risk-based fire safety rules and stronger MSME support. The Bill also introduces automatic appeals for delayed public services and simplifies registration for doctors from other states. These reforms aim to reduce compliance burdens, speed up approvals and promote a business-friendly environment.

Key Points:

- The Gujarat Assembly passed the Ease of Doing Business Bill, 2026, amending 12 provisions across five state laws to simplify business approvals, compliance and government services.
- Key reforms include 24×7 operation of eligible commercial establishments, self-declaration for new business registration, risk-based fire safety norms, expanded MSME facilitation and automatic appeals for delayed public services.
- The Bill also enables quicker registration of doctors from other states through self-declaration, easing professional registration requirements in Gujarat.

5. दक्षिण रेलवे ने ५,०६८ किलोमीटर में १०० प्रतिशत

विद्युतीकरण हासिल किया

- ✖ तमिलनाडु में ७१ किलोमीटर लंबे पट्टुक्कोट्टई-कराईक्कुडी खंड के पूरा होने के बाद दक्षिण रेलवे ने अपने



५,०६८ रूट-किलोमीटर ब्रॉड-गेज नेटवर्क का १०० प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इस खंड को २५ किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन के साथ विद्युतीकृत किया गया और नौ सितंबर, २०२६ को इसका वैधानिक निरीक्षण किया गया। पूर्ण विद्युतीकरण से निर्बाध विद्युत कर्षण संभव होगा, जिससे इंजनों को बदलने की आवश्यकता कम होगी और परिचालन दक्षता, गति एवं इंजनों के उपयोग में सुधार होगा। इससे उत्सर्जन में भी कमी आने की उम्मीद है। यह उपलब्धि दक्षिण रेलवे की १९*१ में शुरू हुई विद्युतीकरण यात्रा के पूरा होने का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु:

- नौ सितंबर, २०२६ को ७१ किलोमीटर लंबे पट्टुक्कोट्टई-कराईक्कुडी खंड के विद्युतीकरण और वैधानिक निरीक्षण के बाद, दक्षिण रेलवे ने अपने पूरे ५,०६८ रूट-किलोमीटर ब्रॉड-गेज नेटवर्क का १०० प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है।
- विद्युतीकृत नेटवर्क २५ किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन का उपयोग करता है, जिससे रेलगाड़ियां इंजन बदले बिना लगातार विद्युत कर्षण पर चल सकेंगी, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार होगा और देरी में कमी आएगी।
- पूर्ण विद्युतीकरण से ट्रेनों की उच्च गति, बेहतर इंजन उपयोग और कम कार्बन उत्सर्जन का समर्थन होने की उम्मीद है, जो १९*१ में शुरू हुई दक्षिण रेलवे की विद्युतीकरण यात्रा के पूरा होने का प्रतीक है।

5. Southern Railway Achieves 100% Electrification Across 5,068 km

- ✖ Southern Railway has achieved 100% electrification of its 5,068 route-kilometre broad-gauge network following the completion of the 71 km Pattukkottai-Karaikkudi section in Tamil Nadu. The section was electrified with 25 kV AC traction and underwent statutory inspection on September 9, 2026. Full electrification will enable uninterrupted electric traction, reducing locomotive changes and improving operational efficiency, speed and locomotive utilisation. It is also expected to lower emissions. The achievement marks the completion of Southern Railway's electrification journey that began in 1931.



Key Points:

- Southern Railway has achieved 100% electrification of its entire 5,068 route-km broad-gauge network, following the electrification and statutory inspection of the 71-km Pattukkottai-Karaikkudi section on September 9, 2026.
- The electrified network uses 25 kV AC traction, enabling trains to operate continuously on electric traction without changing locomotives, improving operational efficiency and reducing delays.
- Full electrification is expected to support higher train speeds, better locomotive utilisation and lower carbon emissions, marking the completion of Southern Railway's electrification journey that began in 1931.

6. भारत ने छह महीनों में एचपीवी टीके की ८० लाख से अधिक खुराकें दीं

भारत के एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम ने फरवरी २०२६ में अपनी शुरुआत के छह महीनों के भीतर ८० लाख खुराकों का आंकड़ा पार कर लिया है। यह



निःशुल्क और स्वैच्छिक कार्यक्रम माता-पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर १४ वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी टीके की एकल खुराक प्रदान करता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने १०० प्रतिशत कवरेज हासिल किया है, जबकि कई अन्य राज्यों ने मजबूत प्रगति दर्ज की है। इस पहल का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम करना है, जो मुख्य रूप से एचपीवी संक्रमण के कारण होता है। विशेषज्ञों ने टीकाकरण के साथ-साथ जागरूकता और नियमित जांच के महत्व पर भी जोर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- भारत के एचपीवी टीकाकरण अभियान ने फरवरी २०२६ में अपनी शुरुआत के छह महीनों के भीतर ८० लाख खुराकों को पार कर लिया, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में १४ वर्ष की लड़कियों को निःशुल्क, स्वैच्छिक एकल खुराक देने का लक्ष्य रखा गया।
- गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने संबंधित लक्षित समूहों का १०० प्रतिशत कवरेज हासिल किया, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश और असम ने ९० प्रतिशत से अधिक कवरेज पार किया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम करना है, जिसमें विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि एचपीवी टीकाकरण के साथ नियमित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच और जन जागरूकता को भी जोड़ा जाना चाहिए।

India Administers Over 80 Lakh HPV Vaccine Doses in Six Months

India's HPV vaccination programme has crossed 80 lakh doses within six months of its launch in



February 2026. The free, voluntary programme provides a single HPV vaccine dose to 14-year-old girls at government health facilities with parental consent. Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Mizoram have achieved 100% coverage, while several other states have recorded strong progress. The initiative aims to prevent cervical cancer, which is largely caused by HPV infection. Experts have also stressed the importance of awareness and regular screening alongside vaccination.

Key Points:

- India's HPV vaccination drive crossed 80 lakh doses within six months of its launch in February 2026, targeting 14-year-old girls with a free, voluntary single dose at government health facilities.
- Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Mizoram achieved 100% coverage of their respective target groups, while Bihar, Andhra Pradesh and Assam crossed 90% coverage.
- The programme aims to prevent cervical cancer, with experts stressing that HPV vaccination should be complemented by regular cervical cancer screening and public awareness.

7. रूस ने भारत को उन्नत एसयू-३०एमकेआई इंजन 7.

उन्नयन की पेशकश की

रूस ने भारत के एसयू-३०एमकेआई बेड़े के लिए अपने उन्नत इग्देलिये १७७एस लड़ाकू विमान इंजन को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, जो



संभावित रूप से मौजूदा एएल-३१एफ/एफपी इंजनों का स्थान ले सकता है। १७७एस से समान आकार और वजन बनाए रखते हुए १४.५ टन का थ्रस्ट देने का अनुमान है, जिससे इसे आसानी से एकीकृत किया जा सकेगा। रूस का दावा है कि यह ६,००० घंटे तक काम कर सकता है और ईंधन की खपत में लगभग सात प्रतिशत की कमी कर सकता है। भारत लागत, एकीकरण, रखरखाव और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। यह प्रस्ताव भारत-रूस रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

- रूस ने एसयू-३०एमकेआई बेड़े के उन्नयन के लिए भारत को अपने इग्देलिये १७७एस इंजन का प्रस्ताव दिया है, जो संभावित रूप से मौजूदा एएल-३१एफ/एफपी इंजनों का स्थान ले सकता है। दावा किया गया है कि नया इंजन १४.५ टन का थ्रस्ट, लगभग सात प्रतिशत कम ईंधन खपत और ६,००० घंटे तक का सेवा जीवन प्रदान करता है।
- १७७एस को मौजूदा इंजनों के समान आयाम और वजन के साथ डिजाइन किया गया है, जो सीमित संरचनात्मक संशोधनों के साथ सुखोई परिवार के विमानों में इसके एकीकरण की अनुमति दे सकता है।
- भारत और रूस द्वारा रक्षा और एयरोस्पेस सहयोग को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के बीच, भारत लागत, तकनीकी एकीकरण, रखरखाव आवश्यकताओं और परिचालन लाभों के आधार पर प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा।

Russia Offers Advanced Su-30MKI Engine Upgrade to India

Russia has proposed developing its advanced Izdeliye 177S fighter engine for India's Su-30MKI fleet, potentially replacing the existing AL-31F/FP engines. The 177S is projected to deliver 14.5 tonnes of thrust while maintaining similar size and weight, enabling easier integration. Russia claims it can operate for up to 6,000 hours and reduce fuel consumption by around 7%. India will assess the proposal based on costs, integration, maintenance and operational requirements. The proposal reflects broader efforts to strengthen India-Russia defence and technological cooperation.



Key Points:

- Russia has proposed its Izdeliye 177S engine to India for upgrading the Su-30MKI fleet, potentially replacing the existing AL-31F/FP engines. The new engine is claimed to offer 14.5 tonnes of thrust, around 7% lower fuel consumption, and a service life of up to 6,000 hours.
- The 177S is designed to have dimensions and weight similar to the existing engines, which could allow its integration into Su-family aircraft with limited structural modifications.
- India will assess the proposal based on cost, technical integration, maintenance requirements and operational benefits, amid broader efforts by India and Russia to strengthen defence and aerospace cooperation.

8. रामेश्वरम मंदिर की पृष्ठभूमि ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

को किया सुशोभित

नई दिल्ली में १८वें ब्रिक्स शिखर

सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी ने भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं का स्वागत किया, तो पृष्ठभूमि में रामेश्वरम का रामनाथस्वामी मंदिर प्रमुखता से प्रदर्शित हुआ। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भारत के १२ ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थलों में से एक है और अपने भव्य गलियारों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व ने राजनयिक सभा में भारतीय विरासत का तत्व जोड़ा। बारह और तेरह सितंबर, २०२६ को आयोजित इस शिखर सम्मेलन में समावेशी वैश्वक शासन, बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- नई दिल्ली में १८वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं का स्वागत करने के दौरान पृष्ठभूमि में रामेश्वरम का रामनाथस्वामी मंदिर प्रदर्शित किया गया।
- भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भारत के १२ ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपने भव्य गलियारों तथा द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसने इस राजनयिक आयोजन में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक तत्व प्रस्तुत किया।
- भारत की अध्यक्षता में बारह और तेरह सितंबर, २०२६ को आयोजित १८वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सुरक्षा पर चर्चा के साथ-साथ समावेशी वैश्वक शासन और बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया।

8. Rameswaram Temple Backdrop

Highlights BRICS Summit

The Ramanathaswamy Temple in Rameswaram featured prominently in the backdrop as Prime Minister Narendra Modi



welcomed BRICS leaders at Bharat Mandapam during the 18th BRICS Summit in New Delhi. Dedicated to Lord Shiva, the temple is one of India's 12 Jyotirlinga shrines and is renowned for its grand corridors and architecture. The cultural representation added an Indian heritage element to the diplomatic gathering. The summit, held on September 12-13, 2026, focused on inclusive global governance, multilateralism and international cooperation.

Key Points:

- The Ramanathaswamy Temple in Rameswaram featured in the backdrop at Bharat Mandapam as Prime Minister Narendra Modi welcomed BRICS leaders during the 18th BRICS Summit in New Delhi.
- The temple, dedicated to Lord Shiva, is one of India's 12 Jyotirlingas and is renowned for its grand corridors and Dravidian architecture, bringing an element of Indian cultural heritage to the diplomatic event.
- The 18th BRICS Summit, held under India's chairmanship on September 12-13, 2026, focused on inclusive global governance and multilateralism, alongside discussions on trade, technology, energy and security.

9. आईआरडीएआई ने इंडसइंड बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इंडसइंड बैंक पर उसके बैंकएश्योरेंस संचालन में बीमा से संबंधित शिकायत निवारण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जून २०२२* में किए गए एक निरीक्षण में पाया गया कि बैंक के पास बीमा ग्राहकों के लिए एक समर्पित शिकायत तंत्र का अभाव था, वह नवीनीकरण नोटिस जारी करने में विफल रहा और उसने अपना आईआरडीएआई पंजीकरण नंबर प्रदर्शित नहीं किया था। प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने से पहले प्राधिकरण ने मार्च २०२५ में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक को अपनी शिकायत प्रणाली को मजबूत करना होगा, आदेश को अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और ९० दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।



मुख्य बिंदु:

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इंडसइंड बैंक पर उसके बैंकएश्योरेंस संचालन में बीमा संबंधी शिकायत निवारण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- उल्लंघनों में एक समर्पित बीमा शिकायत तंत्र बनाए रखने में विफलता, पॉलिसी नवीनीकरण नोटिस जारी न करना, अपने मंच पर प्राधिकरण पंजीकरण संख्या का न होना और अपनी वेबसाइट पर अपर्याप्त शिकायत सुविधाएं शामिल थीं।
- प्राधिकरण ने बैंक को अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने, जुर्माने के आदेश को अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखने और ९० दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

9. IRDAI Fines IndusInd Bank Rs. 1 Crore

IRDAI has imposed a Rs. 1 crore penalty on IndusInd Bank for violating insurance-related grievance redressal and reporting requirements in its bancassurance operations. An inspection conducted in June 2023 found that the bank lacked a dedicated grievance mechanism for insurance customers, failed to issue renewal notices and did not display its IRDAI registration number. IRDAI issued a Show Cause Notice in March 2025 before beginning enforcement proceedings. The bank must strengthen its grievance system, present the order to its Board and submit an Action Taken Report within 90 days.



Key Points:

- IRDAI imposed a Rs. 1 crore penalty on IndusInd Bank for non-compliance with insurance-related grievance redressal and reporting requirements in its bancassurance operations.
- The violations included failure to maintain a dedicated insurance grievance mechanism, non-issuance of policy renewal notices, absence of the IRDAI Registration Number on its platform, and inadequate grievance facilities on its website.
- IRDAI has directed the bank to strengthen its grievance redressal system, place the penalty order before its Board and submit an Action Taken Report within 90 days.

10. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने ४१वीं सुरंग सफलता हासिल की

✎ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने ग्यारह सितंबर, २०२६ को १०.८४७ किलोमीटर लंबी एस्केप टनल-एक के पूरा होने के साथ अपनी ४१वीं सुरंग



सफलता हासिल की। उत्तराखंड में १२५ किलोमीटर लंबी ब्रॉड-गेज रेलवे परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा *७,००० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित की जा रही है, जिसे दिसंबर २०२९ तक पूरा करने का लक्ष्य है। सितंबर २०२६ तक, इस परियोजना ने ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति और ९७ प्रतिशत सुरंग उत्खनन हासिल कर लिया था। यह सफलता हिमालयी क्षेत्र की जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाओं के माध्यम से सुरंग बनाने में शामिल इंजीनियरिंग चुनौतियों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु:

- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने ग्यारह सितंबर, २०२६ को परियोजना की दूसरी सबसे लंबी सुरंग, १०.८४७ किलोमीटर लंबी एस्केप टनल-एक के पूरा होने के साथ अपनी ४१वीं सुरंग सफलता हासिल की।
- रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा *७,००० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित की जा रही १२५ किलोमीटर लंबी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन ने सितंबर २०२६ तक ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति और लगभग ९७ प्रतिशत सुरंग उत्खनन प्राप्त कर लिया था।
- इस परियोजना का निर्माण मेन बाउंड्री थ्रस्ट के पास भ्रंशित चट्टान और मायलोनाइट क्षेत्रों सहित चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, और इसे दिसंबर २०२९ तक पूरा करने का लक्ष्य है।



10. Rishikesh-Karnaprayag Rail Project Achieves 41st Tunnel Breakthrough

✎ The Rishikesh - Karnaprayag Rail Project achieved its 41st tunnel breakthrough on September 11, 2026, with the completion of the 10.847-km Escape Tunnel-1. The 125-km broad-gauge railway project in Uttarakhand is being developed by Rail Vikas Nigam Limited at an estimated cost of Rs. 37,000 crore, with completion targeted for December 2029. By September 2026, the project had achieved 78% physical progress and 97% tunnel excavation. The breakthrough highlights engineering challenges involved in tunnelling through the Himalayan region's complex geological formations.



Key Points:

- The Rishikesh-Karnaprayag Rail Project achieved its 41st tunnel breakthrough on September 11, 2026, with the completion of the 10.847-km Escape Tunnel-1, the project's second-longest tunnel.
- The 125-km broad-gauge railway line, being developed by Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) at an estimated cost of Rs. 37,000 crore, had achieved 78% physical progress and about 97% tunnel excavation by September 2026.
- The project is being constructed through challenging Himalayan geological formations, including faulted rock and mylonite zones near the Main Boundary Thrust, and is targeted for completion by December 2029.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS



MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने हाल ही में किस सुरंग के पूरा होने के साथ अपनी ४१वीं सुरंग सफलता हासिल की ?

- (a) एस्केप टनल-एक
- (b) एस्केप टनल-दो
- (c) मेन टनल-एक
- (d) इमरजेंसी टनल-तीन

Q2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बीमा शिकायत निवारण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से संबंधित उल्लंघनों के लिए किस बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया ?

- (a) बैंक ऑफ बड़ौदा
- (b) इंडसइंड बैंक
- (c) एक्सिस बैंक
- (d) यस बैंक

Q3. नई दिल्ली में १८वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रतिष्ठित मंदिर की पृष्ठभूमि के समक्ष ब्रिक्स नेताओं का स्वागत किया ?

- (a) रामनाथस्वामी मंदिर
- (b) मीनाक्षी अम्मन मंदिर
- (c) बृहदेश्वर मंदिर
- (d) सोमनाथ मंदिर

Q4. रूस ने हाल ही में भारत के एसयू-३०एमकेआई बेड़े के लिए अपने उन्नत इज्देलिये १७७एस लड़ाकू इंजन को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित इंजन संभावित रूप से किन मौजूदा इंजनों की जगह ले सकता है ?

- (a) एफ४०४ और एफ४१४
- (b) एम८८-२
- (c) ईजे२००
- (d) एएल-३१एफ/एफपी

Q5. भारत के राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम ने हाल ही में फरवरी २०२६ में अपनी शुरुआत के छह महीनों के भीतर ८० लाख खुराकों का मील का पथर पार किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से किस समूह को लक्षित करता है ?

- (a) १० वर्ष की आयु के लड़के
- (b) १२ वर्ष की आयु की लड़कियां
- (c) १४ वर्ष की आयु की लड़कियां
- (d) २५ वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं

Q1. The Rishikesh-Karnaprayag Rail Project recently achieved its 41st tunnel breakthrough with the completion of which tunnel?

- (a) Escape Tunnel-1
- (b) Escape Tunnel-2
- (c) Main Tunnel-1
- (d) Emergency Tunnel-3

Q2. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) recently imposed a 1 crore penalty on which bank for violations related to insurance grievance redressal and reporting requirements?

- (a) Bank of Baroda
- (b) IndusInd Bank
- (c) Axis Bank
- (d) Yes Bank

Q3. During the 18th BRICS Summit in New Delhi, Prime Minister Narendra Modi welcomed BRICS leaders against a backdrop featuring which iconic temple?

- (a) Ramanathaswamy Temple
- (b) Meenakshi Amman Temple
- (c) Brihadeeswarar Temple
- (d) Somnath Temple

Q4. Russia has recently proposed developing its advanced Izdeliye 177S fighter engine for India's Su-30MKI fleet. Which existing engines could the proposed engine potentially replace?

- (a) F404 and F414
- (b) M88-2
- (c) EJ200
- (d) AL-31F/FP

Q5. India's national HPV vaccination programme recently crossed the milestone of 80 lakh doses within six months of its launch in February 2026. The programme primarily targets which group?

- (a) Boys aged 10 years
- (b) Girls aged 12 years
- (c) Girls aged 14 years
- (d) Women above 25 years

- Q6. दक्षिण रेलवे ने हाल ही में पट्टुक्कोट्टई-कराईक्कुडी खंड के पूरा होने के बाद अपने ब्रॉड-गेज नेटवर्क का १०० प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल किया है। इसके विद्युतीकृत ब्रॉड-गेज नेटवर्क की कुल रूट लंबाई कितनी है?
- (a) ४,०६८ किलोमीटर
(b) ५,६०८ किलोमीटर
(c) ५,०६८ किलोमीटर
(d) ६,०६८ किलोमीटर
- Q7. किस राज्य की विधानसभा ने व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, २०२६ पारित किया?
- (a) गुजरात
(b) महाराष्ट्र
(c) मध्य प्रदेश
(d) पश्चिम बंगाल
- Q8. समुद्र के नीचे की केबल अवसंरचना पर भारत-अमेरिका सहयोग को हाल ही में किस द्विपक्षीय पहल के तहत आयोजित अंडरसी केबल्स कार्यशाला के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था?
- (a) भारत-अमेरिका आईसीईटी पहल
(b) भारत-अमेरिका ट्रस्ट पहल
(c) भारत-अमेरिका २+२ वार्ता
(d) भारत-अमेरिका क्वाड पहल
- Q9. अट्वाइस अगस्त, २०२६ को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ७४०.८०* अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो उस समय का एक नया रिकॉर्ड था। इस वृद्धि में किस घटक ने सर्वाधिक योगदान दिया?
- (a) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां
(b) स्वर्ण भंडार
(c) विशेष आहरण अधिकार
(d) रिज़र्व ट्रेन्च स्थिति
- Q10. केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि कानूनी कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में बैंकिंग अभिलेखों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने वाला बैंकर्स बुक्स एंविडेंस एक्ट, २०२६ किस तिथि से लागू होगा?
- (a) पंद्रह सितंबर, २०२६
(b) एक अक्टूबर, २०२६
(c) एक अप्रैल, २०२७
(d) एक दिसंबर, २०२६

- Q6. Southern Railway recently achieved 100% electrification of its broad-gauge network after the completion of the Pattukkottai-Karaikkudi section. What is the total route length of its electrified broad-gauge network?
- (a) 4,068 km
(b) 5,608 km
(c) 5,068 km
(d) 6,068 km
- Q7. Which state assembly passed the Ease of Doing Business Bill, 2026, aimed at simplifying regulations and reducing compliance burdens for businesses?
- (a) Gujarat
(b) Maharashtra
(c) Madhya Pradesh
(d) West Bengal
- Q8. The India-US cooperation on undersea cable infrastructure was recently advanced through an Undersea Cables Workshop held under which bilateral initiative?
- (a) India-US iCET Initiative
(b) India-US TRUST Initiative
(c) India-US 2+2 Dialogue
(d) India-US QUAD Initiative
- Q9. India's foreign exchange reserves reached \$740.803 billion in the week ended August 28, 2026, marking a fresh record at the time. Which component contributed the most to this increase?
- (a) Foreign Currency Assets
(b) Gold reserves
(c) Special Drawing Rights
(d) Reserve Tranche Position
- Q10. The Central Government recently notified that the Bankers' Books Evidence Act, 2026, which modernises the legal framework governing the use of banking records as evidence in legal proceedings, will come into force from which date?
- (a) September 15, 2026
(b) October 1, 2026
(c) April 1, 2027
(d) December 1, 2026

उत्तरमाला (Answer Key)

- 1 A 2 B 3 A 4 D 5 C 6 C 7 A 8 B 9 A 10 B

